



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152]  
No. 152]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, मार्च 28, 1985/चैत्र 7, 1907  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 1985/CHAITRA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

उद्योग एवम् कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)  
आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1985

का. आ. 257 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./85 —  
केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास  
मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 134 (अ)/18कक/आई. डी.  
आर. ए./79, तारीख 13 मार्च, 1979 द्वारा यथा अपांदिगित  
आदेश सं. का. आ. 529 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./74,  
तारीख 6 सितम्बर, 1974, द्वारा (जिसे हममें इसके पश्चात्  
उक्त आदेश कहा गया है) मंचिब, बन्द मण उद्योग विभाग  
पश्चिमी बंगाल सरकार को (जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुन-  
निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कहा गया है) (जिसे  
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स  
इंडिया वौल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपूर, पश्चिमी  
बंगाल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम  
कहा गया है) तारीख 6 सितम्बर, 1974 से पांच वर्ष की अवधि  
के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि लोकहित में यह  
समीचीन है कि उक्त अधिसूचित आदेश को उपयुक्त पांच वर्ष के

समाप्त होने के बाद प्रभावी बना रहना चाहिए और उसमें 31 मार्च  
1985 तक की, जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, अतिरिक्त  
अवधि के लिए इसे जारी रखने के लिए समय-समय पर निदेश  
जारी किए थे, (देखिए भारत सरकार के औद्योगिक विकास  
विभाग) —

सं. का. आ. 512 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./79,  
तारीख 4 सितम्बर, 1979, सं. का. आ. 749 (अ)/18कक/आई.  
डी. आर. ए./80, तारीख 5 सितम्बर, 1980, सं. का. आ.  
684 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./81, तारीख 4 सितम्बर,  
1981, सं. का. आ. 125 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./  
82, तारीख 5 मार्च, 1982, सं. का. आ. 648 (अ)/18कक/आई.  
डी. आर. ए./82, तारीख 4 सितम्बर, 1982, सं. का. आ.  
158 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 4  
मार्च, 1983, सं. का. आ. 386 (अ)/18कक/आई. डी. आर.  
ए./83, तारीख 31 मई, 1983, सं. का. आ. 937 (अ)/18-  
कक/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 29 दिसंबर, 1983, सं.  
का. आ. 470 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./84, तारीख  
28 जून, 1984, तथा सं. का. आ. 947 (अ)/18कक/आई.  
डी. आर. ए./84, तारीख 18 दिसम्बर, 1984 ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन  
है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त प्राधिकृत व्यक्ति

द्वारा 31 मार्च, 1986 तक की और अवधि के लिए जारी रखा जाए ;

अतः, केंद्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1986 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2 (14)/80-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरवान, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY & C.A.

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 28th March, 1985

S.O. 257(E)|18AA|IDRA|85 —Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)|18AA|IDRA|74, dated the 6th September, 1974 as modified by the Order No. S.O. 134(E)|18AA|IDRA|79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development)).

Nos. S.O. 512(E)|18AA|IDRA|79, dated the 4th September, 1979, S.O. 749(E)|18AA|IDRA|80, dated the 5th September, 1980, S.O. 684(E)|18AA|IDRA|81, dated the 4th September, 1981, S.O. 125(E)|18AA|IDRA|82, dated the 5th March, 1982, S.O. 648(E)|18AA|IDRA|82, dated the 4th September, 1982, S.O. 158(E)|18AA|IDRA|83, dated the 4th March, 1983, S.O. 386(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st May, 1983, S.O. 937(E)|18AA|IDRA|83, dated the 29th December, 1983, S.O. 470(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984, and S.O. 947(E)|18AA|IDRA|84, dated the 18th December, 1984:

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period upto 31st March, 1986;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1986.

[File No. 2(14)|80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.